



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938

No. 274]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ ASADHA 13, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 27 जून, 2016

सं. टीएएमपी/68/2012-बीपीसीएल.— महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान दरमानों की वैधता संलग्न आदेश द्वारा बढ़ाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या. टीएएमपी/68/2012-बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आवेदक

गणपति

(i). श्री टीएस. बालसुब्रमनियन (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2016 के 21वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के वर्तमान दरमानों की वैधता बढ़ाने से संबंधित है।

2.1 बीपीसीएल के वर्तमान दरमान पहली बार इस प्राधिकरण ने दिनांक 4 अगस्त, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी / 68/2012-बीपीसीएल द्वारा अनुमोदित किए गए थे जिसे भारत के राजपत्र में 19 अगस्त, 2014 को अधिसूचित किया गया था। आदेश में मानदरों की वैधता 31 मार्च 2016 तक निर्धारित की गई थी।

2.2 बीपीसीएल द्वारा अपने 9 मार्च, 2016 के पत्र में किए गए अनुरोध के आधार पर इस प्राधिकरण ने अपने 30 मार्च, 2016 के आदेश के द्वारा बीपीसीएल के दरमानों की वर्तमान वैधता को 30 जून, 2016 तक बढ़ा दिया था। यह आदेश भारत के राजपत्र, में राजपत्र संख्या 152 दिनांक 25 अप्रैल, 2016 में अधिसूचित किया गया था।

3. अब, बीपीसीएल ने अपने 16 जून, 2016 के पत्र के द्वारा यह सूचित किया है कि वे अपना प्रस्ताव अभी बना रहे हैं और वे उक्त कार्य को पूरा कर 15 जुलाई, 2016 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इस संदर्भ में बीपीसीएल ने उनके वर्तमान दरमानों को 31 अगस्त, 2016 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
- 4.1 बीपीसीएल को अभी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। उसने अपना प्रस्ताव 15 जुलाई, 2016 तक प्रस्तुत करने का समय मांगा है। बीपीसीएल द्वारा दायर किए जाने वाले प्रस्ताव की संवीक्षा की जाएगी और संबंधित हितधारकों से परामर्श भी करना होगा। प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात मामले के अंतिम निपटान तक इस पर कौंफी समय लगेगा और इस तथ्य को मान्य करते हुए कि बीपीसीएल के वर्तमान दरमानों की वैधता 30 जून, 2016 को समाप्त हो रही है, बीपीसीएल के वर्तमान दरमानों की वैधता को 30 जून, 2016 से आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- 4.2 इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि बीपीसीएल ने 31 अगस्त, 2016 तक विस्तार करने की वांछा प्रकट की है। तथापि, प्रस्ताव में निहित परामर्शी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त समझा जाता है कि वैधता को 30 सितम्बर, 2016 तक बढ़ाया जाए। निःसंदेह यदि बीपीसीएल के प्रस्ताव का निपटान पहले हो जाता है तो बीपीसीएल के लिए निर्धारित की जाने वाली दरें 30 सितम्बर, 2016 से पहले प्रभावी हो सकती हैं।
- 4.3 उक्त स्थिति को देखते हुए, यह प्राधिकरण बीपीसीएल के विद्यमान दरमानों की वैधता का विस्तार 30 सितम्बर, 2016 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख जो भी पहले हो तक विस्तार करता है।
5. 1 अप्रैल, 2016 के बाद की अवधि के लिए बीपीसीएल को उपाजित अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, का संव्यवहार महापत्तन न्यास, 2015 की नई प्रशुल्क नीति से अधिशेषित होगा।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन-III/4/असा./143/16(156)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 27th June, 2016

No. TAMP/68/2012-BPCL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/68/2012-BPCL

The Bharat Petroleum Corporation Limited - - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 21 day of June 2016)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) in the Jawaharlal Nehru Port Trust.

- 2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of BPCL was first approved by this Authority vide Order No. TAMP/68/2012-BPCL dated 4 August 2014 which was notified in the Gazette of India on 19 August 2014. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2016.

2.2. Based on the request made by the BPCL vide its letter dated 9 March 2016, this Authority vide its Order dated 30 March 2016 had extended the validity of the existing SOR of BPCL from the date of its expiry till 30 June 2016. This Order was notified in the Gazette of India dated 25 April 2016 vide Gazette No. 152.

3. Now, the BPCL vide its letter dated 16 June 2016 has stated that, they are still in the process of formulating their proposal and that they will be completing the aforesaid working and would be submitting by 15 July 2016. In this context, the BPCL has also requested us to grant the extension of rates till 31 August 2016.

4.1. The BPCL is yet to file its proposal. It has sought time till 15 July 2016 to file its proposal. The proposal to be filed by BPCL has to be scrutinized and taken on consultation with the relevant stake holders. Given that it would take time after the receipt of proposal for the case to mature for final disposal and recognizing that the extended validity of the existing SOR of BPCL expires on 30 June 2016, it is necessary to extend the validity of the existing SOR of BPCL beyond 30 June 2016.

4.2. In this connection, it is relevant to mention here that the BPCL has sought extension of time upto 31 August 2016. However, considering the consultation procedure involved, it is felt appropriate to extend the validity upto 30 September 2016. Nevertheless, in the event of final disposal of the BPCL case earlier, the rates to be fixed for BPCL may come into effect earlier than 30 September 2016.

4.3. In view of the above position, this Authority extends the validity of the existing SOR of BPCL upto 30 September 2016 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier. The BPCL is advised to file its proposal positively by 15 July 2016, as agreed by it.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2016, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16(156)]